

प्रश्न- बांग्लादेश के प्रति भारत का दृष्टिकोण किस प्रकार उसके प्रथम पड़ोसी की नीति को प्रदर्शित करता है और इससे बांग्लादेश जैसे देश में चीन के बढ़ते प्रभाव को कहाँ तक कम करने में सहायता मिलेगी? विवेचना कीजिए।

(250 शब्द)

How does India's views towards Bangladesh reflects its neighbour first policy and to what extent it will help in reducing the growing influence of China in a country like Bangladesh. Give arguments.

(250 Words)

मॉडल उत्तर

उत्तर:- वर्ष 1971 में शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश का उदय एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ। जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग ने बांग्लादेश में पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी राज्य की स्थापना की, जिसे भारत का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। यद्यपि कुछ समय पश्चात् बांग्लादेश में लोकतांत्रिक विचारधारा का स्थान कट्टरता तथा तानाशाही ने ले लिया तथा 1975 से 1990 तक जिया-उर-रहमान तथा इरशाद जैसे सैन्य तानाशाहों के नेतृत्व में बांग्लादेश में भारत विरोधी वातावरण तैयार हुआ। यद्यपि भारत ने बांग्लादेश के साथ पड़ोसी प्रथम तथा गुजराल डॉक्ट्रिन के अनुसार निरंतर समन्वयकारी व्यवहार किया।

1990 में बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हुई तथा भारत ने संबंध बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। दोनों देशों के मध्य गंगा नदी के जल बंटवारे, तीस्ता नदी जल विवाद, अंतः क्षेत्र मामला आदि प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आपसी बातचीत के द्वारा सहमति बनी है तथा इस दिशा में और सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

- भारत ने बांग्लादेश के प्रति उदार रवैया ही अपनाया है। इसका विशेष उदाहरण फरक्का समझौते में देखा जा सकता है। यह समझौता 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा तथा बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के मध्य हुआ। भारत ने जनवरी से मई के दौरान स्वयं को 40,000 क्यूसेक जल, जबकि बांग्लादेश को 67000 क्यूसेक जल देना स्वीकार किया।

तीस्ता नदी जल विवाद पर भी 1983 में तदर्थ जल समझौता किया गया है। जिसके तहत नदी के 75 प्रतिशत जल का बंटवारा किया गया, जिसमें 42.5 प्रतिशत जल भारत तथा 37.5 प्रतिशत जल बांग्लादेश को मिलेगा। यद्यपि इस पर अभी दोनों देशों में मतभेद हैं क्योंकि बांग्लादेश पानी के आधे विभाजन की बात करता है।

- अंतः क्षेत्रीय गलियारों पर दोनों देशों के मध्य 2011 में समझौते पर सहमति अमल की गई तथा 2015 में संसद ने 119 वाँ संविधान संशोधन पारित कर इस समस्या का निदान कर दिया। विश्व में शांतिपूर्ण सीमा समझौते का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है यह समझौता।
- भारत एवं बांग्लादेश के मध्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध भी प्रगति पर हैं। भारत ने 2015 में 25 वस्तुओं को छोड़कर बांग्लादेश की सभी वस्तुओं को भारत में शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। साथ ही एक-दूसरे के साथ लोगों के आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए रेल तथा बस संचार को बढ़ावा दिया है।
- भारत ने बी.सी.आई.एम. तथा बिम्स्टेक व सार्क संगठनों जैसे क्षेत्रीय मंचों से बांग्लादेश के साथ समग्र संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया है। यद्यपि पाकिस्तान तथा चीन ने यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया है ताकि भारत को प्रतिसंतुलित किया जा सके। चीन कुनमिंग योजना के जरिए म्यांमार के रास्ते चटगांव तक 900 किमी. लंबा राजमार्ग बना रहा है, ताकि बांग्लादेश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाया जा सके। इसके अलावा बांग्लादेश चीन से सबसे अधिक मात्रा में हथियारों का आयात करता है। चीन बांग्लादेश को परमाणु ऊर्जा विकसित करने में भी सहायता कर रहा है।

यद्यपि भारत की सहयोगपूर्ण नीति तथा बांग्लादेश की उपलब्ध करायी गई एकतरफा सहायता दोनों देशों के मजबूत संबंधों को प्रदर्शित करती है। वर्तमान समय में दोनों देशों के मध्य संबंध प्रगाढ़ हैं तथा बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने भी अपने यहाँ से किसी भी भारत विरोधी मुहिम न पनपने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस प्रकार वर्तमान तक चीन के बढ़ते प्रभाव को भारत अपनी सहयोगकारी एवं संतुलित विदेश नीति के माध्यम से प्रतिसंतुलित करने में सफल रहा है।